

बी0 एन0 एस0, 2023 की चुनौतियाँ

*डॉ0 संजीव गंगवार,
सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, फर्रुखाबाद
ज्योति, शोध छात्रा

विधि मेजर मेजर एस0डी0 सिंह विश्व विद्यालय फर्रुखाबाद

शोधसार: यह शोध पत्र भारत के नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) के लिए संदर्भित है जो भारतीय न्याय व्यवस्था में 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए हैं, जिसने एक वर्ष का सफर पूरा कर लिया है इन नये कानूनों को भारतीय समसामयिक परिप्रेक्ष्य व भविष्योन्मुखी रूप में तैयार किया गया, जिनसे शीघ्र न्याय की अपेक्षा की गई, जिसके अर्न्तगत लोगों की समसामयिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप एक ऐसी कानूनी संरचना का निर्माण किया गया है, जो नागरिक केंद्रित होने के साथ नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें यह नए कानून पुलिस को जवाबदेह बनाते हुए पीड़ित-केंद्रित हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में यह देखने का प्रयास किया गया कि जिस नये कानून को लागू हुए एक वर्ष पूरा होने जा रहा है उसके किर्यान्वयन में कौन सी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, जिनको समय रहते जानना नये कानूनों के सफल किर्यान्वयन के लिये आवश्यक है, जिससे हमारी संसद द्वारा बनाये कानून अपने नागरिकों को शीघ्र न्याय की सुविधा प्रदान कर विश्व पटल पर अपनी पहचान स्थापित कर सके।

आवश्यक सूचना :- “कृपया अनुरोध है कि शोध पत्र में जानकारी का इस्तेमाल कानूनी दस्तावेज के रूप में न करें”

बीज, शब्द—आई0पी0सी0, सी0आर0पी0सी0, भारतीय न्याय संहिता, 2023 बी0एन0एस0, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 बी0एन0एस0एस0

प्रस्तावना— सभ्य समाज के निर्माण में सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण स्थान रखता है दुनिया के आज उन्ही देशों ने प्रगति हासिल की है जिन्होंने अपनी न्यायिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर अपने नागरिकों को समय से न्याय प्रदान करने में माहिरता हासिल कर ली है, इन देशों में कानून निर्माण व संशोधन की प्रक्रिया बहुत लोचपूर्ण देखने को मिलती है, दण्ड व्यवस्था में भी मानवीय मूल्यों का पूरा पालन किया जाता है न्यायालयों का भी यह प्रयास रहता है कि देश के किसी भी नागरिक को न्याय लेने में बेवजह समय व धन की वरबादी न हो तथा लोगों का न्यायालयों के प्रति विश्वास बना रहे, इसी लिये इन देशों के नागरिकों में सकारात्मक राष्ट्रवाद की भावना व राष्ट्रीय प्रेम अधिक देखने को मिलता है, तथा नागरिक अपने देश के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, और आज इसी के बल पर इन देशों ने विकसित देशों की श्रेणी में पहचान स्थापित की है जिसमें न्यायिक व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसके फलस्वरूप इन देशों में वकालत का पेशा सर्व श्रेष्ठ व सम्मानित श्रेणी में माना जाता है भारत में इस पेशे को किस नजरीये से देखा जाता है और क्या

क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता लेखक को यह सब लिखने की शायद आवश्यकता नहीं है।

किन्तु वर्तमान भारत सरकार देश में न्याय व्यवस्था के सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है जिसके क्रम में वर्षों से अंग्रेजों के द्वारा भारतीय नागरिकों को दण्ड व न्याय देने वाले छलावापूर्ण कानूनी संहिता को पूर्ण रूप से हटा दिया है जिसका पूरा श्रेय वर्तमान गृह मंत्री मा0 अमित शाह जी को जाता है, बैसे भी भारतीय समाज वर्षों से अंग्रेजों के बनाये दण्डान्तमक कानूनी व्यवस्था से तृप्त हो इसको बदलने की आवाज, दबी जवान से उठाता रहा है किन्तु इसको बदलने की हिमायत स्वतन्त्र भारत कि किसी सरकार ने नहीं की यही कारण है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त आये हमारे संविधान में 100 से अधिक संशोधन किये जा चुके हैं जबकि भारतीय दण्ड संहिता में 1860 से, 163 वर्षों में आई0पी0सी0 में मात्र 75 के लगभग ही संशोधन किये गये जिसमें 1985 के उपरान्त आई0पी0सी0 में कोई अधिकारिक संशोधन नहीं हुआ इससे पूर्व 1973 में अपराधिक प्रक्रिया संहिता सी0आर0पी0सी0, 1973 लाकर जरूर कुछ बदलाव किये गये जबकि अन्य संशोधन आंशिक ही रहे

है।आई0पी0सी0 की दण्डात्मक व भारतीये नागरिकों को कोर्ट कचहरी में उलझाएँ रखने की अंग्रेजियत मंशा से निजात दिलाने का प्रयास किसी भी सरकार ने नहीं किया । **यह पहली बार है कि किसी सरकार ने अंग्रेजों द्वारा दिये कानून को उखाड़ फेंकने की हिमायत कर 2023 में न्याय व्यवस्था व पुलिस तंत्र को नए कानून उपलब्ध करा भारतीय नागरिकों को न्याय व सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदान की।**

इन तीन पुराने कानूनों में बदलाव लाने हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 2019 से ही गहन विचार-विमर्श शुरू कर किया था जिनको लेकर प्रबुद्धजीवियों व विधि,वेत्ताओं के साथ कर्नाटक व केरल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी0एस0 मलिमथ की अध्यक्षता में गठित "मलिमथ" समिति जिसका अधिकारिक नाम "अपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर समिति"था, इसका गठन 24 नवंबर 2000 में किया गया,साथ ही रणबीर सिंह समिति ,राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली में भी एक समिति का गठन कर अपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों का सुझावों के लिये नियुक्त किया गया था इन सबके द्वारा गृह मंत्रालय को 3200 सुझाव प्राप्त हुए जिन पर गृह मंत्री मा0अमित शाह जी ने सभी सुझावों संशोधनों पर सूक्ष्मता से विचार करते हुए इन तीनों कानूनों पर विचार,विमर्श करने के लिये 158 बैठकें कर कानून निम्नप्रण प्रक्रिया को पूर्ण कर **भारत को नये कानूनों भारतीय न्याय संहिता,2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम,2023 की सौगात प्रदान की।** जिसको 25 दिसम्बर 2023 को मा0राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के उपरान्त कानूनी जामा प्रदान कर पुराने कानूनों की जगह नये कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया।

विशेषताएं— सर्वप्रथम विशेषता मे **भारतीय न्याय संहिता का लक्ष्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों और राज्य के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता देना है** इसको बी0एन0एस0,2023 के नाम से जाना जाता है जिसमें 20 अध्याय व 358 धाराएं हैं जिसने भारतीय दण्ड संहिता 1860 का स्थान लिया जिसमें 511 धाराएं व 23 अध्याय थे।इसी प्रकार

सी0आर0पी0सी0,1973 के स्थान पर जिसमें 484 धाराएं व 37 अध्याय थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 बी0एन0एस0एस0 ने स्थान लिया जिसमें 39 अध्याय व 531धाराएं हैं।तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने लिया है जिसमें 170 धाराएं व 12 अध्याय हैं।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को विशेष अध्याय-5 को प्राथमिकता से समर्पित :- नवीन कानून में **महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध और उनकी सुरक्षा पर एक अध्याय-5 जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 में राज्य के खिलाफ अपराध को समर्पित था उसे महिलाओं और बच्चों के लिए समर्पित किया गया है** जिसके अन्तर्गत पूर्ववर्ती दण्ड संहिता 1860 में **विखरी धाराओं जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध और उनकी सुरक्षा पर आधारित थी उन्हें एक साथ (धारा-63 से 99 तक)लाया गया है** साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र की **बच्चीयों से दुष्कर्म पर आजीवन व मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान कर महिलाओं के साथ झूठे वादे कर दुष्कर्म को जंघन्य अपराध माना गया।**

दण्ड को मानवीय बनाने के साथ-साथ पुनर्वास पर जोर :-नये कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत **प्रतिशोधात्मक सिद्धान्तों पर पुनर्विचार कर मौत,आजीवन कारावास कारावास,संपत्ति की जब्ती और जुर्माने के साथ बी0एन0एस0 की धारा,4(च) की शुरुआत एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है जिसमें सजा का छठा रूप सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया।**

अपराधीयों को कठोर सजा का प्रावधान :- दण्ड को मानवीय बनाने का तात्पर्य यह नहीं है कि नई कानूनी व्यवस्था अपराधी को बेदाग छूट देगी बी0एन0एस0 के तहत 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है तथा 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है सामुदायिक सेवा के लिए दण्ड सिर्फ छह अपराधों में पेश किया गया है,और अनावश्यक 19 धाराओं को अधिनियम से निरस्त या हटा दिया गया।

आधुनिक न्याय प्रणाली व नई प्रौद्योगिकी से लैस :-
नए कानून भारत में एक आधुनिक न्याय प्रणाली पर आधारित है जिसमें जीरो एफ0आई0आर0, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सम्मन और लोक सेवकों व पुलिस आदि साक्षियों का श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से गवाही के बिकल्प की व्यवस्था (बी0एन0एस0एस0 की धारा-254(2)) साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व डिजिटल साक्ष्य को प्राथमिकता तथा सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी (बी0एन0एस0एस0 की धारा-176(3)) जैसे प्रावधान जो अंग्रेजों के औपनिवेशिक का पूर्ण परिवर्तन व प्राचीनता का पुनरुद्धार और न्याय क्षेत्र में आधुनिकता की नई छलांग है और अब न्याय व्यवस्था केवल दण्ड पर आधारित न हो, बल्कि न्याय पर भी ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

समयाविधि का प्रावधान :- नये अधिनियम में न्याय मिलने की एक सैद्धांतिक समय सीमा निर्धारित की गई जैसे कि पीड़ित को 90 दिनों के भीतर अन्वेषण की प्रगति की जानकारी देना 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र व बहस पूर्ण होने के उपरान्त 30 जिसे अधिकतम 45 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान किया गया है। (बी0एन0एस0एस0 की धारा-258) ऐसा प्रावधान पूर्व अधिनियम की सी0आर0पी0सी0, 1973 में भी था किन्तु नये साक्ष्य अधिनियम से यह पूर्ण अपेक्षा है कि अधिनियम की मंशा के अनुरूप पीड़ितों को समय-सीमा से न्याय मिल सकेगा।

इसी प्रकार भारतीय नवीन कानूनी अधिनियम कई विशेषताओं से परिपूर्ण हैं जिसे गृह मंत्री मा0अमित शाह जी के द्वारा अनुभवी विधि वेत्ताओं द्वारा तैयार कर कानून निम्राण की संसदीय प्रणाली को अपना एक जुलाई दो हजार चौबिस को नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) को शीघ्र न्याय देने के उद्देश्य से समर्पित कर दिया गया, जिसे लागू हुए एक वर्ष पूर्ण हो चुका है ऐसे में स्वभाविक है कि एक वर्ष के दौरान वह

चुनौतियां सामने आ चुकी होंगी जो इसके सफल क्रियान्वयन में आड़े आ रही होंगी जिनको जानने का प्रयास प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है जो निम्नवत हैं-

पुलिस विभाग की चुनौतियाँ- किसी कानून का पालन व समाज में लॉ एण्ड ऑर्डर बनाये रखने व लोगों से कानून का पालन कराये जाने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की ही होती है, और यह सब तभी हो संभव हो सकता है कि जब हम पुलिस को कानूनी रूप में प्रशिक्षित कर हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित कर तैयार करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि नये कानून जल्द रचनात्मक प्रभाव दिखाएं तो इसके लिये जितनी जल्दी हो पुलिस को उन समस्याओं से निजात दिलाई जाये जो नवीन कानून लागू करने में आड़े आ रही हैं जैसे :-

- 1-पुलिस के पास आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुपलब्धता। जैसे- कैमरा टैबलेट, बाडी कैमरा मोबाइल आदि।
- 2-आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित बर्दी।
- 3-फॉरेंसिक लेवों की कमी।
- 4-प्रशिक्षण का अभाव।
- 5-नवीन व पुराने अधिनियमों का दवाव।
- 6-आधुनिक सरकारी उपकरणों के अभाव में निजी मोबाइलों का उपयोग।
- 7-ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में सी0सी0टी0वी0 कैमरों का अभाव।
- 8-समाज में निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साक्ष्य देने पर संकोच करना।
- 9-जन सामान्य में नये कानून के प्रति जागरूकता अभाव।
- 10-पुलिस के पास हाईटेक उपकरणों से सुसज्जित वहानों व पुलिस स्टेशनों का अभाव। आदि ऐसी कई चुनौतियों का सामना पुलिस को करना पड़ रहा है

फिर भी उपलब्ध संसाधनों पर हमारी पुलिस कार्य कर रही है और आशा है कि जल्द ही इन समस्याओं से पुलिस को निजात मिल जायेगी।

न्यायालयों की चुनौतियाँ :- बैसे तो नये कानूनों के प्रति न्यायालयों ने अपने आप को तैयार कर शीर्ष न्याय देने के सिद्धांतों के पालन करने के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सम्मन और लोक सेवकों व पुलिस आदि साक्षियों का श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से गवाही आदि नये अधिनियमों की मंशा अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, फिर भी कुछ चुनौतियों का सामना न्यायालयों को करना पड़ रहा है जैसे की :-

1- न्यायालयों के साहायक कर्मचारियों में नये कानून के प्रति प्रशिक्षण का अभाव।

2- स्थाई तकनीकी कर्मचारियों का अभाव।

3- इलेक्ट्रॉनिक व डिजीटल साक्ष्य सुरक्षित डाटा स्टोर का अभाव।

4- आईपीसी, 1860 व बीएनएस, 2023 दोनों कानूनों के प्रकरणों का एक ही कोर्ट में चलने से कार्य का दबाव।

5- नये कानूनों के प्रति अधिवक्ताओं को जानकारी का अभाव। आदि चुनौतियों का सामना न्यायालयों को करना पड़ रहा है।

किशोर न्याय बोर्ड की चुनौतियाँ:- 1- स्टेनों कर्मचारी की अनुपलब्धता।

2- स्थाई स्टाफ का अभाव।

3- साहायक कर्मचारियों में नये कानून के प्रति प्रशिक्षण का अभाव।

4- स्थाई कम्प्यूटर आपरेटर की अनुपलब्धता।

5- आईपीसी, 1860 व बीएनएस, 2023 दोनों कानूनों के प्रकरणों का एक ही साथ चलने से कार्य का दबाव।

6- किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 6 के अनुपालन में किशोर न्याय बोर्ड न्यायालय व कारागार परिसर से दूरी बनाये रखने में न्यूनतम व अधिकतम सीमा न होने से कई जनपदों में 5 से 25 किलो मीटर दूरी पर संचालन बोर्ड की एक सबसे बड़ी चुनौती है जो नये कानूनों के शीर्ष न्याय देने के सिद्धान्त को प्रभावित कर रही है। जबकि किशोर न्याय बोर्ड का संचालन न्यायालय पर आश्रित है न्यायालय व अधिवक्ताओं तथा अभियोजन विभाग के सहयोग के बिना बोर्ड का संचालन संभव नहीं हो सकता।

उक्त आदि चुनौतियों का सामना किशोर न्याय बोर्ड को करना पड़ रहा है जिनका प्रभाव नये कानूनों के सफल क्रियान्वयन पर पड़ रहा है।

निष्कर्ष एव सुझाव :- इस प्रकार नये कानूनों का एक वर्ष का सफर इसकी क्रियान्वित संस्थाओं का काफी खट्टे मीठे अनुभवों भरा रहा है, और जो चुनौतियाँ आ रही उनसे भी समय रहते निजात मिल जायेगी आशा है कि जैसे-जैसे पुराने कानून से सम्बन्धित प्रकरणों का निपटान होता जायेगा बैसे बैसे नवीन कानून न्याय पर अपनी पकड़ बनाता जायेगा फिर भी कुछ सुझाव नये कानूनों प्रगति में वेहतर कारगर साबित हो सकते हैं।

सुझाव :- 1- सर्वप्रथम भविष्य को ध्यान में रखते हुए देश के सभी शिक्षण संस्थानों में विशेष रूप से विधि के पाठ्यक्रमों में (एलएलबी, एलएलएम, आदि) भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को सम्मिलित किया जाना अतिआवश्यक है।

2- नये कानून में इलेक्ट्रॉनिक व डिजीटल साक्ष्य की विशेष प्राथमिकता को देखते हुए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायतों व नगर पंचायतों द्वारा तथा निजी व्यावसायिक केन्द्रों, निजी प्रतिष्ठानों, ढाबों के सम्पूर्ण भारत को यूरोप सऊदी की तरज

पर सार्वजनिक कैमरों को क्षेत्र के थानों ऑनलाइन जोड़ा जाये जिससे आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रानिक व डिजीटल साक्ष्य आसानी प्राप्त किया जा सके।

3—पुलिस को कानूनी रूप में प्रशिक्षित कर हाईटेक सुविधाओं से जिसमें विदेशी मॉडल पर आधुनिक उपकरणों के साथ बर्दी, बाड़ी कैमरा व कैमरा युक्त हैलमट आदि से पुलिस को सुसज्जित किया जाये।

4— अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बिधिक सेवा प्राधीकरण, गैर सरकारी संस्थाओं तथा बार एसोसिएशन तथा बिधि महाविद्यालयों,

विश्वविद्यालयों को सेमिनार व गोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- 1—भारतीय न्याय संहिता,2023
- 2— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023
- 3— भारतीय साक्ष्य अधिनियम,2023)
- 4— भारतीय दण्ड संहिता 1860
- 5—सी0आर0पी0सी0,1973
- 6— भारतीय साक्ष्य अधिनियम,2023)

*Corresponding Author: Dr. Sanjeev Kumar Gangwar

E-mail: sanjeevgangwar827@gmail.com

Received: 03 June,2025; Accepted: 28 July 2025. Available online: 30 July, 2025

Published by SAFE. (Society for Academic Facilitation and Extension)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License

